दिनांक : 01 फरवरी 2014

कांग्रेस और तेलंगाना

– अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

एक अलग तेलंगाना राज्य के गठन का प्रस्ताव अब संसद में चर्चा के लिए आने वाला है। भाजपा हमेशा से तेलंगाना राज्य के गठन के प्रस्ताव का समर्थन करती रही है। साथ ही, हमारा मानना है कि सीमान्ध्र क्षेत्र के साथ भी न्याय होना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस मुद्दे से निपटा है उससे शासन कला में उसका अनाड़ीपन पूरी तरह झलकता है। वर्ष 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने तीन राज्यों उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन करने का फैसला किया। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन तीनों राज्यों के गठन से उन क्षेत्रों को मदद मिली जिनके फायदे के लिए इन राज्यों का गठन किया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री श्री एल के आडवाणी ने इन तीनों राज्यों के गठन में अहम भूमिका निभाई। छत्तीसबढ़ और उत्तराखंड के गठन में किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा जबकि झारखंड के गठन के समय बिहार में सत्तारुढ़ आरजेडी ने शुरु में परेशानी खड़ी की। गृह मंत्री ने सभी राज्यों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया। प्रत्येक राज्य को यह बात अच्छी तरह समझाई गई कि नये राज्यों के गठन से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें आश्वासन दिया गया कि अलग राज्य की कमियों को पूरा किया जाएगा। तीनों राज्यों की विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिये। इसके बाद संसद के दोनों सदनों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और आम सहमति से तीनों राज्यों के गठन को मंजूरी दे दी गई। तीनों नये राज्यों से जुड़े अंदरुनी मुद्दों का भी सावधानीपूर्वक निपटारा किया गया। देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया। नैनीताल में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करके अल्मोड़ा की क्षतिपूर्ति की गई। रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया और बिलासपुर में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित की गई। वर्तमान इमारतों को रातों रात नया रुप दिया गया ताकि वहां सचिवालय और उच्च न्यायालय परिसर स्थापित किए जा सकें। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। किसी भी राज्य में एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ। उच्च न्यायालय की पीठों के उद्घाटन के लिए कानून मंत्री के रुप में मैंने इन तीनों राज्यों का दौरा किया। लोगों के बीच उत्सव का सा माहौल था। वे एनडीए का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने चुनाव में किया गया अपना वादा पूरा किया। आंध्र प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वह इसके विपरीत है। तेलंगाना और सीमान्ध्र दोनों क्षेत्रों को कांग्रेस के इरादों पर संदेह है। पर्याप्त तैयारी नहीं की गई। सीमान्ध्र के लोगों के मन में अन्याय को लेकर जो भावना पैदा होने की संभावना थी, उस पर गौर नहीं किया गया। इस मुद्दे को समझने और नये राज्य के गठन में संतुलन बनाने के लिए जिस दक्ष राजनैतिक प्रबंधन की आवश्यकता थी वह नहीं दिखाई दी। दोनों ही क्षेत्रों में अफरा–तफरी की स्थिति है। सत्तारुढ़ दल खुद ही विभाजन के कगार पर है। राज्य विधानसभा ने केन्द्र के प्रस्ताव पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जिस आम सहमति की जरुरत थी वह भी नहीं ली गई। नेकनीयत से जिस तेलंगाना का गठन होने से लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति होती वह राजनैतिक कुप्रबंधन के कारण विवाद में पड़ गया।

अभी भी देर नहीं हुई है। दोनों क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखकर बिजली, सिंचाई और सीमान्ध्र के लिए नई राजधानी के संभावित गठन के मुद्दे पर न्याय किया जाना चाहिए। एक अच्छा काम जिसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया, हित को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आवश्यक कार्य किया जाएगा और तेलंगाना नया सवेरा देखेगा।

*****